भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-18

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज

† ***18. श्री मलैयारासन डी.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 374 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के चयन के क्या मानदंड हैं;
(घ) तमिलनाडु राज्य में चिह्नित किए गए ऐसे जिलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ङ) तमिलनाडु के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में ऐसे डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और इन्हें पूरा करने की समय-सीमा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा इन नए स्थापित संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्याप्त अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

माननीय संसद सदस्य श्री मलैयारासन डी. द्वारा 'शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों' के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च): राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के प्रति उनकी अनुरूपता सुनिश्चित कर उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए, रूसा के पिछले चरण की देय राशि सहित 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। पीएम- उषा के तहत, फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। फोकस जिलों की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिनमें निम्न सकल नामांकन अनुपात, लिंग समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रवृत्त जिले आदि शामिल हैं।
इस योजना का उद्देश्य विभिन्न घटकों, जैसे बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुदान (जीएसयू), महाविद्यालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुदान (जीएससी), नए आदर्श डिग्री महाविद्यालय (एनएमडीसी) और लैंगिक समावेशन एवं समानता पहल (जीआईईआई) के अंतर्गत सहायता के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुँच, समानता और उत्कृष्टता में सुधार लाना है। पीएम-उषा के अंतर्गत सभी 615 इकाइयों को विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 8178.71 करोड़ रुपये की राशि के साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुमोदित किया गया है।

तमिलनाडु राज्य में, रूसा के तहत, विभिन्न घटकों के अंतर्गत 526 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता वाली कुल 99 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 85 परियोजनाएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तमिलनाडु राज्य का बजट आवंटन रूसा के पिछले चरणों की प्रतिबद्ध देयताएं पूरा करने के लिए 25.5 करोड़ रुपये है।

****